3245 (10)
9-11-20

कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार एवं भारत विभाजन

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की
इतिहास विषय में
पी–एच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध–प्रबन्ध का सारांष

शोध निर्देशक
डॉ. संजय कुमार सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग
एम.एम.एच. कॉलेज, गाजियाबाद

शोधकर्ता
अभिषेक प्रियदर्शी

शोध केन्द्र
इतिहास अध्ययन एवं शोध केन्द्र
एम.एम.एच. कॉलेज, गाजियाबाद

2020

शोध–सार

राज्यों का विभाजन एक मानवीय समस्या है, जोकि सीमाओं के बलात परिवर्तन की मांग करता है। विभाजन की मांग तब की जाती है जब दो नस्ली समुदाय किसी राज्य विशेष पर अधिकार के लिए सशस्त्र संघर्ष पर उतरते हैं। भारत का विभाजन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक ताने–बाने में पैदा की गई जटिलताओं के कारण हुआ। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप का यह बंटवारा 19वीं शताब्दी के मध्य से भारत में विकसित हुई राष्ट्रवाद की पराजय तथा सांप्रदायिकता की जीत थी।

15 अगस्त 1947 को भारतीय उपमहाद्वीप का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के रूप में किया गया। सांप्रदायिक आधार पर किए गए इस विभाजन ने अकल्पनीय मानवीय त्रासदी को जन्म दिया। सदियों से साथ रहकर हिंदुस्तानी संस्कृति का निर्माण करने वाले हिंदुओं और मुसलमानों को यह बताया गया कि सह–अस्तित्व दोनों धर्मों की नियति नहीं है।

ध्यातव्य है कि विभाजन से पूर्व के भारतीय राजनीति में सत्ता के मुख्यतः तीन दावेदार थे। उनमें से हर किसी को विभाजन से जोड़ा जाता है और उनमें से हर किसी ने विभाजन से बचने का प्रयास किया है तथा अन्य दावेदारों पर इसका दोषारोपण किया है। विभाजन से संबंधित इतिहास लेखन की प्रवृत्ति भी किसी न किसी एक दावेदार सत्ता समूह को विभाजन का नायक तथा दूसरे को खलनायक बनाने की रही है।

भारत में कांग्रेस के लिए विभाजन की जिम्मेवारी से मुक्त होना इसलिए संभव था क्योंकि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संघर्ष पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था अतः राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में कांग्रेस को विभाजन की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान समर्थक मुस्लिम इतिहासकारों ने मुसलमानों को हिंदू हिंसा के उत्पीड़ित वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। पाकिस्तान के इतिहास लेखन में विभाजन का खलनायक कांग्रेस, गांधी तथा नेहरू को माना गया है। दोनों ही राष्ट्रों के इतिहास लेखन में एक प्राकृतिक

उत्तरदायित्व औपनिवेशिक राज्य को भी बना दिया गया है, जो सत्ता में होने के कारण सांप्रदायिकता और उससे जुड़ी हुई हिंसा को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रही थी।

इस शोध में विद्यमान इतिहास लेखन में हावी वैचारिक समस्याओं की वस्तुनिष्ठ आलोचना करते हुए एक संतुलित आकलन का प्रयास किया गया है। इस आकलन की प्रथम अवधारणा यह है कि जनवादी भावनाओं को नकारकर विभाजन पूर्वकाल में सभी राजनीतिक दावेदार सत्तावादी हो चुके थे। चाहे वह कांग्रेस नेतृत्व हो अथवा जिन्ना या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता खोती हुई ब्रिटिश सरकार। सबके लिए प्रमुख लक्ष्य तत्कालिक जनभावना नहीं थी। 'मुक्ति' या 'आजादी' के सपने को पूरा करने के हठ में एक उन्माद की राजनीति की जा रही थी, जहां गांधीवादी रचनात्मक कार्यों और स्वतंत्रता संग्राम की तमाम लड़ाई से परे स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय 'सत्ता समीकरण' प्रमुख हो चुके थे। इस शोध कार्य में इस सवाल को निरंतरता से समझने का प्रयास किया गया है कि क्या 'आजादी' मात्र एक रूमानी ख्याल था जिसे बार–बार यथार्थवाद की राजनीति से परिचित होना पड़ा अथवा आजादी एक मानवगत विषय है। विभाजन पूर्व की धारणाएं बार–बार यह सिद्ध करती है कि राजनीतिक यथार्थ ने क्षणिक हिंसा को जन्म दिया, जिससे धर्म के नाम पर न्यायोचित सिद्ध किया गया। परंतु तमाम दावेदारों के यथार्थ के बावजूद विभाजन का निहितार्थ धर्म नहीं अपितु राजनीति थी। क्योंकि यदि 'विभाजन' का मूल कारण धर्म होता तो 1947 के उपरांत 1971 में भाषाई आधार पर एक और यथार्थवादी विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ती।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध ''कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार एवं भारत विभाजन', भारतीय उपमहाद्वीप के त्रासदीपूर्ण विभाजन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश सरकार की भूमिकाओं के निष्पक्ष मूल्यांकन का एक विनम्र प्रयास है।

Abhishek Priyadarshi

अभिषेक प्रियदर्शी